राजेश बिंदल से पहले, जे।

भारत संचार निगम सीएडी– याचिकाकर्ता

बनाम

कर्मचारी' प्रोविडेंट फंडअपीलीय ट्रिब्यूनल

और एक और- उत्तरदाता

सीडब्ल्यूपीएनओ। 2011 की 7612

सितम्बर 3,2012

A. भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 226 - रिट अधिकारिता -कर्मचारी' भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 - Ss. 7-Q & 14-B - भविष्य निधि की देय राशि में देरी से जमा करना - ब्याज वसूलना याचिकाकर्ता राज्य के स्वामित्व वाला निगम - अपील के मनोरंजन के लिए प्रीडिपॉजिट -धारा 7-क्यू और 7-ए - पूर्ववर्ती शर्त के रूप में मांग का 30% जमा करना वसूली रहने के लिए और अपील के मनोरंजन के लिए नहीं - में कोई अवैधता नहीं इस संबंध में अधिकरण का आदेश।

माना जाता है कि आक्षेपित आदेश यह नहीं दर्शाता है कि यह एक पूर्व शर्त थी

अपील के मनोरंजन के लिए। धारा 7-ओफ्थे एक्ट, जो अधिकरण द्वारा अपील के मनोरंजन के लिए पूर्व शर्त, प्रदान करता है कि पहले की गई मांग की राशि का 75% जमा करने की शर्त अपील का मनोरंजन उन मामलों में होता है जब मांग आदेश पारित करके उठाई जाती है अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत। वर्तमान मामले में, ट्रिब्यूनल ने यह सोचा याचिकाकर्ता को एक के रूप में उठाई गई मांग का 30% जमा करने के लिए कहना उचित है शर्त केवल वसूली रहने के लिए और मनोरंजन के लिए नहीं मोहक गुण। इस आदेश में उस सीमा तक कोई अवैधता नहीं है।

(पैरा 9)

B. भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - अभ्यास और प्रक्रिया -ऑडी अल्टरम पार्टेम का सिद्धांत - इसके तीन आवश्यक दोहराए गए - गूढ़ ट्रिब्यूनल का आदेश, जो अंतिम फैक्टफाइंडिंग प्राधिकरण है - की आवश्यकता अनिवार्य के रूप में पहचाने जाने वाले कारणों का संकेत - हर के दिल की धड़कन का कारण निष्कर्ष और अदालत द्वारा दिमाग के आवेदन को इंगित करता है - यह कानूनी रूप से भी एक आदेश को बनाए रखता है - ट्रिब्यूनल के आक्षेपित आदेश को केवल जमीन पर अलग रखा गया कि यह गैर-बोल रहा था। आयोजित, कि ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांत में तीन बुनियादी हैं|अत्यावश्यक वस्तुएं। सबसे पहले, एक व्यक्ति जिसके खिलाफ एक आदेश पारित किया जाना आवश्यक है, उसे अवश्य करना चाहिए सुनवाई का अवसर दिया जाए। दूसरे, संबंधित प्राधिकारी एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करनी चाहिए और अंत में, प्राधिकरण को संबंधित को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी तर्क या द्वारा मामले का निपटान करना चाहिए बोलने का आदेश।

(पैरा 11)

आगे कहा गया कि गुप्त आदेश पारित करने के संबंध में मुद्दा था|माननीय द्वारा माना गया' उच्चतम न्यायालय ने बार-बार ऐसा किया है। यह कहा गया था कि कारणों को इंगित करने की आवश्यकता को न्यायिक रूप से अनिवार्य माना गया है।कारण हर निष्कर्ष की धड़कन है और उसी के बिना, यह निर्जीव हो जाता है। के आवेदन को इंगित करने के लिए कम से कम पर्याप्त कारण न्यायालय के समक्ष मामले पर ध्यान देना एक ठोस न्यायिक का एक अनिवार्य हिस्सा है प्रणाली। यह प्रभावित पक्ष को यह जानने में सक्षम बनाता है कि निर्णय इसके खिलाफ क्यों गया है उसे। यह केवल तर्क है जो एक उच्च या अपीलीय अदालत को सक्षम कर सकता है|मुद्दे में विवाद को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझें और पकड़ें क्या प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया तर्क, जिसका आदेश है|आक्षेपित है, कानून में टिकाऊ है। कारणों को दर्ज न करने से दोहरा हो सकता है दुर्बलता; सबसे पहले, यह प्रभावित पक्ष के लिए पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है और दूसरी बात,विशेष रूप से, न्याय के उचित प्रशासन में बाधा। " कारण" हैं उन सामग्रियों के बीच संबंध जिन पर कुछ निष्कर्ष आधारित हैं और वास्तविक निष्कर्ष। संदर्भ ऑटो पिस्टन एमएफजी. कंपनी (पी) लिमिटेड और बनाया जा सकता है|एक अन्य बनाम कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य, निर्णय लिया 30.08.2012 को।

(पैरा 12)

अनिल राठी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए

संजय टांगरी, अधिवक्ता, प्रतिवादियों के लिए।

राजेश बिंदल जे.

(1) प्रादेशिक भविष्य निधि द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.3.2009 आयुक्त, अमृतसर (संक्षेप में, 'आयुक्त') और आदेश दिनांक 13-12-2010, कर्मचारी भविष्य

निधि अपीलीय स्वर्गीय अधिकरण द्वारा पारित (क) को इस न्यायालय के समक्ष आरोपित किया गया है।

(2) संक्षेप में, दलील दिए गए तथ्य यह हैं कि आयुक्त ने एक याचिकाकर्ता को कारण बताने के लिए दिनांक 19-12-2008 को नोटिस दिया गया कि क्यों ब्याज और भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम कर्मचारी भविष्य फंड एपेलेट ट्रिब्यूनल और अन्य कर्मचारी भविष्य निधि की धारा 7क्यू और 14बी के तहत नुकसान नहीं लगाया जाना चाहिए निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (संक्षेप में, 'अधिनियम') खाते पर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उसी का उत्तर दिया गया याचिकाकर्ता वीआईडीसी पत्र दिनांक 4.2.2009। दिनांक 27-3-2009 के आदेश के तहत कमिश्नर ने ब्याज व हर्जाने के मद में 7,24,494/- रुपये का आकलन किया याचिकाकर्ता से वसूली योग्य। पूर्वोक्त आदेश के परिणामस्वरूप,आयुक्त ने दिनांक 3-6-2009 को उपर्युक्त राशि को याचिकाकर्ता ने पंजाब नेशनल बैंक, पठानकोट के साथ बनाए रखा। याचिकाकर्ता अधिकरण के समक्ष दिनांक 27-3-2009 के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की ठहरने के लिए आवेदन। दिनांक 1-7-2009 के आदेश के तहत अधिकरण ने मूल्यांकन की गई राशि का 30%। यह आदेश ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किया गया था|तथ्य यह है कि आयुक्त ने पहले ही मांग की पूरी राशि वापस ले ली थी याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके बैंक खाते से उठाया गया। याचिकाकर्ता ने किया अनुरोध प्रतिवादी नंबर 2 30% की कटौती के बाद 5,07,146/- रुपये की राशि की वापसी के लिए दिनांक 1-7-2009 के अंतरिम आदेश के अनुसार पहले ही वसूल की जा चुकी राशि अधिकरण द्वारा पारित किया गया। चूंकि आयुक्त द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर 2,17,348 रुपये की राशि जमा की गई अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 1-7-2009 के आदेश तथा पत्र का अनुपालन सरकार ने दिनांक 15-9-2009 के कार्यालय ज्ञापन सं 15-9-2009 के कार्यालय ज्ञापन सं 10/2009 के माध्यम से एक और अनुरोध किया था कि राशि पहले ही वापस कर दी जाए याचिकाकर्ता के बैंक खाते से निकाला गया। दिनांक के आदेश के अनुसार दिनांक 13-12-2010 के निर्णय के

अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील अधिकरण द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी। यह है|पूर्वोक्त आदेश, जिसे इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित किया गया है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ब्याज और हर्जाना क्यों कारण बताने के लिए दिनांक 19-12-2008 को नोटिस जारी किया गया

अधिनियम की धारा 7क्यू और 14बी के तहत याचिकाकर्ता पर नहीं लगाया जाना चाहिए याचिकाकर्ता ने दिया जवाब सरकार ने दिनांक 4-2-2009 के पत्र के माध्यम से विशेष रूप से नोटिस में कतिपय त्रुटियों का उल्लेख किया है

और भविष्य निधि बकाया राशि जमा करने में देरी का कारण बताते हुए आगे

जो, अन्य बातों के साथ-साथ, इस कारण से था कि कुछ कर्मचारियों के लिए राशि थी|पहले केंद्र सरकार की जीपीएफ योजना में जमा किया जा रहा है, जो

बाद में इस राशि को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को हस्तांतरित कर दिया गया।यूई ने आगे कहा कि जवाब में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क पर विचार किए बिना,आयुक्त ने पूरी तरह से गैर-बोलने वाले आदेश को पारित करके, की राशि का आकलन किया,धारा 7थ के अंतर्गत ब्याज के कारण रु. 1,80,479/- और धारा 7थ के अंतर्गत रु. 1,80,479/- की राशि (क) क्या यह सच है कि अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत हर्जाने के रूप में 5,44,015/- रुपए की राशि का भुगतान किया गया है; कुल रु. 7,24,494/-

अधिकरण से पहले भी, मुद्दों को विस्तार से उठाया गया था, तथापि, अभी भी

अपील को पूरी तरह से गूढ़ आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जो कि एक तरह से अधिक है एक तर्क की तुलना में सटीक। याचिकाकर्ता एक राज्य के स्वामित्व वाला निगम है।हर्जाना तभी लगाया जाना चाहिए जब यह साबित हो जाए कि कुछ लोग हैं रिया, जो वर्तमान मामले में पूरी तरह से गायब है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि अपील के मनोरंजन के लिए पूर्व जमा की कोई आवश्यकता नहीं थी| धारा 7Q और 14B के तहत ब्याज और क्षति का आकलन करने वाले

आदेश के खिलाफ अधिनियम के अनुसार, लेकिन फिर भी अधिकरण ने 30% जमा करने की शर्त लगाई मांग उठाई गई। वह आदेश को रद्द करने और मामले को वापस लेने के लिए प्रार्थना करता है|नए सिरे से विचार करने के लिए अधिकरण के पास वापस।

(4) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता-प्रतिष्ठान का कवरेज है

विवाद में नहीं। भविष्य निधि बकायों को जमा करने में विलंब भी नहीं हुआ है

झगड़ा करना। एक बार ऐसा होने पर, एक आवश्यक परिणाम के रूप में, अनिवार्य के संदर्भ में अधिनियम के प्रावधान, ब्याज और हर्जाना उद्ग्रहणीय थे। थर्क कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है|उसी को माफ करने के लिए किसी भी अधिकार के साथ निहित है। आयुक्त ने कर्मचारी भविष्य निधि में निर्धारित दरों के अनुसार कड़ाई से गणना की जाती है फंड योजना, 1952। उन्होंने आगे कहा कि यह याचिकाकर्ता के लिए था|ट्रिब्यूनल के समक्ष बताया गया कि इसके खिलाफ मांग की गई राशि कमिश्नर द्वारा पहले ही वसूल कर लिया गया था, स्टे के लिए प्रार्थना की गई थी|अप्रभावी प्रदान किया। उस समय आयुक्त का प्रतिनिधित्व नहीं था|अत अधिकरण के समक्ष उनकी कोई गलती नहीं थी। याचिकाकर्ता को अपना खुद का सेट करना होगा क्रम में घर।

(5) उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि एक आदेश में केवल पृष्ठों की संख्या होगी| यह नहीं दिखाते कि वही बोल रहा है और अच्छी तरह से तर्क कर रहा है। सार रूप में, मामला आयुक्त के साथ-साथ अधिकरण द्वारा भी विचार किया गया था। एक बार कानूनी रूप से नहीं टीएलआईसी याचिकाकर्ता द्वारा स्थायी तर्क उठाया गया था, अधिक पैराग्राफ जोड़ दिया गया था आदेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई मांग की राशि 1000 करोड़ रुपये नहीं है। 7,24,494/- रुपये, बल्कि, यह 9,05,273/- रुपये है, जैसा कि आदेश से भी स्पष्ट है आयुक्त का। तथापि, उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि 10,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। याचिकाकर्ता

के खाते से 7,24,494/- रुपये निकाले गए और आगे एक राशि इसके बाद इसके द्वारा 2,17,348/- रुपये जमा किए गए। उन्होंने बर्खास्तगी के लिए प्रार्थना की रिट याचिका।

(6) पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना और कागजी किताब का अवलोकन किया।

(7) याचिकाकर्ता एक राज्य के स्वामित्व वाला निगम है। कोई विवाद नहीं है कि यह अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर किया गया है। को जारी नोटिस में19.12.2008 को याचिकाकर्ता को कारण बताने के लिए कि ब्याज और नुकसान क्यों नहीं है(क) के विलंबित जमा के कारण अधिनियम की धारा 7क्यू और 14ख के अंतर्गत लगाए गए भविष्य निधि और अन्य बकाया, उस अवधि का विवरण जिसके लिए राशि थी|देर से जमा किया गया था। याचिकाकर्ता ने जवाब दिया उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस इस तथ्य सहित सूचना प्रस्तुत करता है कि कुछ कर्मचारियों को पहले जनरल के पास राशि जमा की जा रही थी केंद्र सरकार की भविष्य निधि योजना, हालांकि, बाद में वे (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; औरउनका ऋण भविष्य निधि संगठन के पास जमा किया गया था । कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए गए थे। दिनांक 27.3.2009 के आदेश के तहत, आयुक्त ने केवल दर्ज किया कि उन्होंने मामले की सावधानीपूर्वक जांच की थी और उस रुचि को पाया था और भुगतान में विलंब के कारण हर्जाना उद्ग्रहणीय है । राशि थी धारा 7थ के तहत ब्याज के कारण 1,80,479/- रुपये और धारा 7 क्यू के तहत ब्याज के कारण 1,80,479 /(ख) अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत क्षति के कारण 5,44,015/- रुपए की क्षतिपूत के लिए 5,44,015/- रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। कुल मिलाकर,राशि 7,24,494/- रुपये है।

(8) पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता नेअधिकरण के समक्ष अपील। दिनांक 1-7-2009 के आदेश के तहत अधिकरण ने अपील की और आयुक्त को नोटिस जारी किया। आक्षेपित आदेश का संचालन कर निर्धारण की गई राशि का 30% जमा करने के अध्यधीन रोक लगाई गई थी। हालांकि, तथ्य, जो विवाद में

नहीं है, वह यह है कि पूर्वोक्त आदेश पारित होने से पहले अधिकरण के मामले में आयुक्त ने पहले ही पूरी राशि वसूल कर ली थी|याचिकाकर्ता का पंजाब नेशनल बैंक, पठानकोट में खाता है 3.6.2009 को। इस खाते पर दोष के साथ निहित है याचिकाकर्ता। मामले में, राशि, आदेश के संदर्भ में पहले आक्षेपित अधिकरण को पहले ही वसूल कर लिया गया था, याचिकाकर्ता को इससे अवगत कराना चाहिए था इस तथ्य के बारे में वकील जो ट्रिब्यूनल के समक्ष बयान दे सकते थे तदनुसार। जैसा कि याचिकाकर्ता ने पहले आक्षेपित आदेश पर रोक लगाने के लिए प्रार्थना की थी ट्रिब्यूनल ने मूल्यांकन की गई राशि का 30% जमा करने का निर्देश दिया। वही याचिकाकर्ता का आचरण इस तथ्य से और स्पष्ट है कि संपूर्ण के बावजूद ट्रिब्यूनल के समक्ष आक्षेपित मांग की राशि पहले ही वसूल की जा चुकी थी,फिर भी याचिकाकर्ता को राशि का 30% और जमा करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि अधिकरण द्वारा आक्षेपित आदेश के प्रचालन पर रोक लगाने का निदेश दिया गया है। एक तरह से याचिकाकर्ता ने उठाई गई मांग का 130% जमा किया।

(9) आक्षेपित आदेश यह नहीं दर्शाता है कि यह एक पूर्व शर्त थी|अपील का मनोरंजन। अधिनियम की धारा 7-0, जो पूर्व शर्त से संबंधित है अधिकरण द्वारा अपील के मनोरंजन के लिए यह प्रावधान है कि अपील के मनोरंजन से पहले की गई मांग की राशि का 75% जमा करना (क) की धारा 7क के अधीन आदेश पारित करके मांग की जाती है ढोंग। वर्तमान मामले में, ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता से पूछना उचित समझा केवल रहने के लिए पूर्ववर्ती शर्त के रूप में उठाई गई मांग का 30% जमा करना वसूली और अपील के मनोरंजन के लिए नहीं। में कोई अवैधता नहीं है उस हद तक आदेश।

(10) जहां तक गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने का संबंध है, एक नंगे आक्षेपित आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता पर न तो आयुक्त द्वारा विचार किया गया और न ही ट्रिब्यूनल द्वारा। अधिकरण द्वारा पारित आदेश, जो अंतिम तथ्यान्वेषी प्राधिकरण है, पूर्णत है रहस्यमय।

(11) ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांत में तीन बुनियादी अनिवार्यताएं हैं।सबसे पहले, एक व्यक्ति जिसके खिलाफ एक आदेश पारित किया जाना आवश्यक है, होना चाहिए सुनवाई का अवसर दिया। दूसरे, संबंधित प्राधिकारी एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करनी चाहिए और अंत में, प्राधिकरण को संबंधित को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी तर्क या द्वारा मामले का निपटान करना चाहिए बोलने का आदेश।

(12) गुप्त आदेश पारित करने के संबंध में मुद्दे पर विचार किया गया था| माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार-बार यह कहा है। यह राय दी गई थी कि आवश्यकता कारणों को इंगित करने के लिए न्यायिक रूप से अनिवार्य माना गया है। कारण हर निष्कर्ष की धड़कन है और उसी के बिना, यह निर्जीव हो जाता है। के आवेदन को इंगित करने के लिए कम से कम पर्याप्त कारण न्यायालय के समक्ष मामले पर ध्यान देना एक ठोस न्यायिक का एक अनिवार्य हिस्सा हैप्रणाली। यह प्रभावित पक्ष को यह जानने में सक्षम बनाता है कि निर्णय इसके खिलाफ क्यों गया है उसे। यह केवल तर्क है जो एक उच्च या अपीलीय अदालत को सक्षम कर सकता है मुद्दे में विवाद को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझें और पकड़ें क्या प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा अभिलिखित तर्क, जिसका आदेश है आक्षेपित है, कानून में टिकाऊ है। कारणों को दर्ज न करने से दोहरा हो सकता है दुर्बलता; सबसे पहले, यह प्रभावित पक्ष के लिए पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है और दूसरी बात,विशेष रूप से, न्याय के उचित प्रशासन में बाधा। "कारण" हैं उन सामग्रियों के बीच लिंक जिन पर कुछ निष्कर्ष आधारित हैं और वास्तविक निष्कर्ष। संदर्भ 2011 के सीडब्ल्यूपी नंबर 1526 का किया जा सकता है- ऑटो पिस्टन एमएफजी कंपनी (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण और अन्य पर दिनांक 30.08.2012 को निर्णय दिया गया।

(13) यदि अधिकरण द्वारा पारित आदेश की सिद्धांतों पर जांच की जाती है|

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, यह एक बोलने वाले आदेश की श्रेणी, इसलिए, अकेले इस स्कोर पर अलग रखी जानी चाहिए

और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए ट्रिब्यूनल को वापस भेजा जाना है। दोनों पक्षों को सुना। तदनुसार आदेश दिया।

(14) पक्षकारों को अपने वकीलों के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया जाता है|आगे की कार्यवाही के लिए दिनांक 1112012 को अधिकरण को एक आदेश जारी किया गया।

(15) वर्तमान मामले में, कुल 7,24,494/- रुपये की मांग उठाई गई थी |ब्याज के कारण दिनांक 27-3-2009 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ और हर्जाना, जो आयुक्त द्वारा बैंक खाते से वसूल किया गया था|याचिकाकर्ता ने 3-6-2009 को पंजाब नेशनल बैंक, पठानकोट में अपना पक्ष रखा।अधिकरण के समक्ष अपील दायर करते समय आक्षेपित व्यक्तियों के स्थगन के लिए प्रार्थना की गई थी आदेश दिया गया था। हालांकि जिस तारीख को स्टे के लिए आवेदन आया था|1-7-2009 को सुनवाई के दौरान स्थगन की प्रार्थना निरर्थक हो गई थी|मांग की संपूर्ण राशि 3-6-2009 को पहले ही वसूल कर ली गई थी। फिर भी

मामले को ट्रिब्यूनल के संज्ञान में नहीं लाया गया है, यह निर्देश दिया गया है आक्षेपित के परिचालन को रोकते हुए उठाई गई मांग का 30% जमा करना आदेश। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 28.7.2009 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया आयुक्त को अपने से पहले से वसूल की गई अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए 30% से अधिक खाता, आई.सी. रु. 5,07,146/-. वही नहीं किया है, अपने ज्ञान में, याचिकाकर्ता 2,17,348/- रुपये की अतिरिक्त राशि आयुक्त के पास 30% के रूप में जमा की। अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसार मूल्यांकित कुल राशि पत्र दिनांक 15.9.2009 को जारी किया गया और अनुरोध किया गया कि 7,24,494/- रुपये की राशि पहले ही इसके बैंक खाते से वसूली वापस की जाए। लेकिन अतिरिक्त राशि वसूल की गई आज तक वापस नहीं किया गया है।

(16) हालांकि उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने उठाने की मांग की

यह प्रस्तुत करते समय कि यह 1000 करोड़ रुपए है, मूल्यांकन की गई राशि के संबंध में विवाद को समाप्त कर दिया गया है।तथापि, यह तर्क गलत है। इसमें कोई शक नहीं, की भाषा आयुक्त द्वारा पारित आदेश भ्रामक है, हालांकि, तालिका ब्याज और क्षति के रूप में मूल्यांकन की गई राशि स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह 1,80,479/- रुपये है।ब्याज के रूप में और नुकसान के रूप में 5,44,015/- रुपये; कुल रु. 7,24,494/-

(17) इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता की ओर से गलती है|अतिरिक्त राशि जमा की, अर्थात, रु. 2,17,348/-अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन इस तथ्य के बावजूद कि संपूर्ण राशि पहले ही वसूल की जा चुकी थी। लेकिन फिर भी तथ्य यह है कि जबकि दिनांक 15.9.2009 के पत्र के साथ उपरोक्त राशि जमा करना, एक अनुरोध 7,24,494/- रुपये की राशि वापस करने के लिए आयुक्त को कहा गया था, जो पहले ही बरामद किया जा चुका था। आयुक्त को यह पता लगाने की आवश्यकता थी कि तथ्य, जो हालांकि पहले से ही उनके ज्ञान में था, और वापस करना चाहिए था कम से कम 2,17,348/- रुपये, वह राशि जो अधिक वसूली गई थी याचिकाकर्ता के खिलाफ उठाई गई मांग। आज की स्थिति के अनुसार, याचिकाकर्ता उस राशि की वापसी। यह उस पर ब्याज प्राप्त करने का भी हकदार है, जो होना चाहिए उसी दर पर जिस पर भविष्य निधि संगठन ब्याज प्रभारित करता है| भविष्य निधि बकायों की विलंबित जमा राशि का लेखा-जोखा।

(18) तदनुसार, यह निदेश दिया जाता है कि आयुक्त एक वापसी करेगा याचिकाकर्ता को 1.10.2009 से 2.10,2009 तक ब्याज सहित 2,17,348 रुपये की राशि राशि वापस कर दी जाती है। ब्याज उसी दर पर होगा जिस पर यह है भविष्य निधि बकायों को देरी से जमा करने पर प्रभारित किया जाता है।

(19) तदनुसार याचिका का निपटारा किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनीषा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
बहादुरगढ़,हरियाणा